

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् 104, महात्मा गांधी मार्ग पर दिनांक 24-3-81 को  
 30 बजे पूर्वान्ह में हुई उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् की वर्ष 1981 की  
 तीसरी बैठक का कार्यवृत्त।

उत्त उपस्थित थे: -

श्री बी०जे० खोदायजी		अध्यक्ष
श्री दयानन्द व्यास	सदस्य, विधान परिषद्	सदस्य
श्री जे०पी० दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
श्री भगवती प्रसाद वर्मा	प्रबन्ध निदेशक जल निगम	सदस्य
6) श्री दुर्गा बहादुर श्रीवास्तव	उप सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
7) श्री शशि कान्त जैन	अनु सचिव, स्थायत्त शासन	सदस्य
श्री कमल पाण्डे	आवास आयुक्त	सदस्य

बैठक की कार्यवाही पर विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये: -

क्र०सं०	विषय	संख्या सं०	निर्णय
1	2	3	4

दिनांक 12-2-81 को परिषद्  
 मुख्यालय पर हुई बैठक के  
 कार्यवृत्त की पुष्टि।

11/(1)/81

परिषद् के कार्यवृत्त के मद संख्या-4 के  
 निर्णय में निम्नलिखित जोड़ते हुये पुष्टि की  
 गई: -  
 0.25% कमिटेमेंट चार्जेंज भी लिये जायें।

परिषद् की बैठक दिनांक  
 12-2-81 के कार्यवृत्त की  
 अनुपालन आख्या।

11/(2)/81

परिषद् द्वारा दिनांक 12-2-81 को हुई  
 बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या का  
 अवलोकन किया गया और निम्नलिखित निर्देश  
 दिये गये: -

- 1- वाहनों को क्रय करने के संबंध में शासन स्तर पर शीघ्रता करायी जाय तथा शासन के आवास विभाग से निवेदन किया जाय कि वाहन क्रय करने के संबंध में सार्वजनिक उपक्रमों के संबंध में अलग से नीति बनाकर संशोधित आदेश जारी किये जाय जिससे कि वाहनों के आभाव में कार्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
- 2- सहायक निदेशक (प्रचार) के पद के संबंध में उपसमिति की संस्तुतियां परिषद् की अगली बैठक में अवश्य प्रस्तुत की जायें।
- 3- विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारियों के पदों के सृजन के संबंध में आवास सचिव के स्तर पर एक बैठक तुरन्त करायी जाय।
- 4- मुरादाबाद में परिषद् द्वारा निर्मित विभिन्न आयु वर्ग के भवनों में पुलिस, सी०आर०पी० एवं पी०एच०सी० द्वारा अनाधिकृत अध्यासन के संबंध में परिषद् ने पिछली बैठक में लिये गये निर्णय की पुष्टि की और आग्रह किया कि इस मामले को शासन स्तर पर उठाया जाय।
- 5- राम सागर मिश्र नगर के 80 मध्यम आयु वर्ग एम०एच०-75 प्रकार के भवनों के प्राविधिक सम्परोक्षण के संबंध में सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्तर पर एक बैठक शीघ्र करायी जाय और ऐसा करने के लिये एक निश्चित अवधि भी निर्धारित की जाय।
- 6- वर्क साइट रजिस्टर यथाशीघ्र खुलवाया जाय।
- 7- कोलोनीज के रख-रखाव के लिये सचिव, स्थायत्त शासन के स्तर पर एक बैठक पुनः करायी जाय तथा शिष्य में जो आवासीय कालोनियां नगरपालिका की सीमा अथवा उसके बाहर बनायी जा रही है अथवा बनायी जायेंगे उनके सम्बन्ध में भी आवास एवं विकास परिषद् के अधिनियम के प्राविधनों के अन्तर्गत सम्पूर्ण सूचना

*(Handwritten Signature)*

- स्वायत्त शासन विभाग को उपलब्ध करा दी जाय जिससे कि कालोनीज के बनाये जाने पर उनके हस्तान्तरण की समस्या उत्पन्न न हो।
- 8- परिषद के तर्जों का कम्प्यूटराइजेशन कारनि के लिये 'स्टडी ग्रुप' की संस्तुतियाँ अगली बैठक में अवश्य प्रस्तुत की जाय।
- 9- 'कारपोरेट प्लान' परिषद की अगली बैठक में अवश्य प्रस्तुत हो।
- 10- आगरा की कमलानगर आवास योजना में ग्राम लखार पुर में स्थित कारबला कमेटी द्वारा मांगी जा रही 9 एकड़ भूमि के मामले में स्थानीय आवास मंत्रे जी की अध्यक्षता में एक बैठक कराया जाय। इस बैठक के लिये एक back ground नोट भी तैयार कर लिया जाय और यह भी निश्चित हो कि किस-किस को आमंत्रित करना है।
- 11- परिषद को सिविल लाइन्स भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, बरेली के विकास कार्यों के प्रोक्कलन की श्चिकृति के संबंध में मुख्य अभियन्ता की रिपोर्ट अगली बैठक में अवश्य प्रस्तुत की जाय।
- 12- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद रेगुलेशन फॉर दी ग्रान्ट आफ दिस विल्डिंग स्ट्रक्चर्स टू दि इम्प्लाइज्ज आफ द परिषद 1973 के संबंध में गाइड लाइन्स परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाय।
- 13- परिषद द्वारा विभिन्न शहरों में निर्मित आवासीय भवनों में से कुछ प्रो प्रोसेसदी भवन जरूरतमन्द लोगों को तुरन्त आवंटित करने हेतु आवास आयुक्त को अधिकृत करने के संबंध में परिषद सदस्य श्री दयानन्द व्यास ने कर्ता कि सार्वजनिक उद्देश्यों के निदेश परिषद पर बाइन्डिंग नहीं होने चाहिये, इस पर शासन के आदेश प्राप्त किये जायें।
- 14- शीम ताल भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, शीमताल के संबंध में जल सम्पत्ति के लिये सिवाई विभाग से सम्पर्क स्थापित करे जिससे कि योजना का कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व जल सम्पत्ति की समस्या का समाधान हो सके।
- 15- रिवालाविंग फण्ड के संबंध में गठित उप-समिति में वित्त विभाग के प्रतिनिधि के स्म में विभाग के उप सचिव श्री दुबे को पत्र भेजा जाय।
- 16- परिषद की गत बैठक के कार्यवृत्त के मद संख्या-52 पर परिषद अधिनियम में संशोधन के संबंध में शासन स्तर पर अग्रतर कार्यवाही सुनिनिश्चित की जाय।
- 17- परिषद के मध्यम आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग भवन निर्माण योजना के अन्तर्गत विनियमावली में प्रयुक्त भूमि का तात्पर्य 'कृत्' से लिये जाने के संबंध में जीवन बीमा निगम आदि से जानकारी प्राप्त कर परिषद को अगली बैठक में अवगत कराया जाय।

) वर्ष 80-81 का पुनरीक्षित  
संव 81-82 का आय-व्ययक

11/(3)/81

परिषद ने सर्वसम्मति से बजट के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

*Handwritten signature*

परिषद् योजनाओं में विदेशी मुद्रा देने वालों के लिये भवन/भूखण्डों का आरक्षण। 11/(4)/81

/वालों को भी वरीयता प्रदान करते हुए

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् भूखण्डों तथा भवनों के पंजीकरण एवं प्रदेशन संबंधी विनियम 1979 के विनियम-11 एवं 46 में संशोधन का प्रस्ताव। 11/(5)/81

परिषद् द्वारा निर्मित भवनों/भूखण्डों के प्रदेशन में आरक्षण वर्ग के अन्तर्गत आने वाले हल्कक क्रेताओं को लाटरी द्वारा सम्मिलित किया जाना। 11/(6)/81

परिषद् द्वारा प्रदियुक्त सम्पत्ति के अन्तर्गत के संबंध में। 11/(7)/81

निर्माण कार्य की समीक्षा (28 फरवरी, 1981 तक) 11/(8)/81

परिषद् ने निर्देश दिये कि विदेशी मुद्रा के संबंध में पूर्ण टिप्पणी के साथ विस्तृत सुझाव परिषद् के समक्ष उनकी अगली बैठक में लाया जाय। फिलहाल मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग में 25 प्रतिशत तक भवन की सम्पत्ति भूखण्डों को सम्मिलित करते हुए एक मुक्त भूगतान करने वालों के लिये और बंधित कर ली जाय तथा इस सम्पत्ति में विदेशी मुद्रा में भवन लेने/प्रदेशन हेतु रखा जाय।

परिषद् ने इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

परिषद् ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

परिषद् ने इस प्रस्ताव पर सर्व-सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया तथा इस प्रस्ताव के साथ सलमन गाइड लाइन्स का भी अनुमोदन किया।

दिनांक 23-3-81 को परिषद् की उपसमिति ने निर्माण कार्य की समीक्षा की। इस समीक्षा में निम्नलिखित विन्दुओं पर विचार कर निर्देश दिये गये: -

- 1- निम्नलिखित 16 नगरों के प्रस्ताव परिषद् के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित करने हेतु दिनांक 6-12-80 तथा 11-2-81 को उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्ताव भेजे गये: -
  - 1- गाजिया बाद
  - 2- ललित पुर
  - 3- टांडा
  - 4- नजीबाबाद
  - 5- नगीना
  - 6- बलराम पुर
  - 7- सिक्दरा बाद
  - 8- कन्नौज
  - 9- मरुगानीपुर
  - 10- कोच
  - 11- कैराना
  - 12- चाँद पुर
  - 13- तिलहर
  - 14- आवुला
  - 15- सहीला
  - 16- बहेड़ी

- 2- शासन स्तर पर शीघ्र आदेश जारी करने के लिये संबंधित उप सचिव से सम्पर्क स्थापित कर अग्रतर कार्यवाही करायी जाय। रानी खेत में भूमि प्राप्त करने के लिये अध्यक्ष तथा आवास आयुक्त की ओर से व्यक्तिगत प्रयास किये जायें। रानी खेत स्थित सरिया कमाण्डर से बात-चीत की जाय और माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री जी को पत्र लिखा जाय तथा आवास सचिव की ओर से रक्षा सचिव, भारत सरकार को भी पत्र भेजा जाय।

दिलक़शा वालोनी में रक्षा विभाग से भूमि प्राप्त करने के लिये मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन स्तर पर एक बैठक आयोजित करायी जाय।

*Farid*

2	3	4
		3- मसूरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ तथा हमीर-पुर नगरों में भूमि चयन के लिये 2 सर्वे की टीमें बताई जाय तथा यह कार्य अप्रैल 1981 तक समाप्त कर दिया जाय। इसी प्रकार तराई क्षेत्र में स्थित बुढ़नी, नौगढ़, नौतनवा, तथा अन्य सभी तराई क्षेत्र के नगरों में भी सर्वे टीमों द्वारा जून के अन्त तक खत चयन करने का प्रयास किया जाय।
		4- देवबन गोपेश्वर तथा गोलाकर्णनाथ नगरों के धारा-28 के प्रस्ताव परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत किये जाय।

### भूमि अध्याप्ति

उप समिति ने वर्ष 1980-81 में भूमि अध्याप्ति कार्यों की समीक्षा की। वर्ष 1980-81 में 5000 एकड़ भूमि प्राप्त करने का लक्ष्य था जिसके विरुद्ध 1100 एकड़ भूमि पर कब्जा 31-3-1981 तक प्राप्त किया जायेगा कानपुर आगरा, लखनऊ तथा वाराणसी महानगरियों में 3245 एकड़ भूमि पर शीघ्र अर्जन कार्यवाही करने के लिये शासन से धारा 7/17 के आदेश जारी करवाये गये जिसके फलस्वरूप आगामी 4 महीनों में इन महानगरियों में कब्जा प्राप्त करने का निम्नलिखित कार्यक्रम बनाया गया:-

नाम	माह अप्रैल-जुलाई 81 तक प्रत्याशित (एकड़ में)			
	अप्रैल, 81	मई, 81	जून, 81	जुलाई, 81
पुर	300	- - -	300	100
गरा	165	400	400	- -
खनऊ	- -	750	- -	375
राणसी	- -	- -	455	- -
त योग	465	1150	1155	475

- 2- महानगरियों में भूमि का कब्जा प्राप्त करने के लिये विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी की सहायता के लिये अतिरिक्त स्टाफ आवश्यकता-नुसार लगाया जाय।
- 3- वर्ष 1981-82 के लिये 5000 एकड़ भूमि अध्याप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- 4- छोटे नगरों में जहाँ भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही अन्तिम दौर में है तथा जहाँ पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या अधिक है वहाँ भी विशेष प्रयत्न से भूमि पर कब्जा प्राप्त किया जाय।

### भूमि विकास कार्य

- 1- वर्ष 1980-81 का 612 एकड़ का पुनरोचित लक्ष्य 31-3-81 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
- 2- वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये 1000 एकड़ भूमि विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

*Lakshmi*

3- धारा-31 से संबंधित प्रस्ताव के लिये संबंधित निकायो, जल संस्थानों, विद्युत् परिषद् जल निगम आदि विभागों की योजना का प्राप्ति बताते हुये पेयजल, सीवर एवं विद्युत् की सुचना भेज दी जाय। मुख्यालय पर इस कार्य का और अच्छे तरीके से समन्वय किया जाय जिससे कि योजनाओं की समाप्ति पर इन विषयों के संबंध में बाधायें उत्पन्न न हों।  
भवन निर्माण एवं भूखण्ड

- 1- परिषद् द्वारा भूखण्ड पुनरीक्षित 10700 भवन तथा 3500 भूखण्डों की पूर्ति 31-3-81 तक हो जाने की संभावना है।
- 2- वर्ष 1981-82 के लिये उपसमिति ने 16000 भवन एवं 4000 भूखण्ड का लक्ष्य निर्धारित किया। इस वर्ष 56000 मीट्रिक टन सीमेंट की मांग के विरुद्ध शासन द्वारा 32500 मीट्रिक टन सीमेंट का ही आवंटन हुआ। इस आवंटित मात्रा में 18170 मीट्रिक टन सीमेंट प्राप्त हो सकी है। शेष सीमेंट को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। सीमेंट को आयातित करने का प्रयास उत्तर प्रदेश निर्माण निगम के साथ मिल कर किया गया था किन्तु इस सीमेंट के प्राप्त होने की संभावना नहीं है।
- 3- परिषद् को कोयले के 2 रेक्स का आवंटन किया गया है किन्तु रेलवे वेगन न मिलने कारण अभी तक कोयला प्राप्त नहीं हो सका है। इस संबंध में माननीय आवास मंत्री जी की ओर से रेल मंत्री जी भारत सरकार को एक पत्र भी भेजा गया है।
- 4- परिषद् द्वारा 'लाइम पोजोलोना प्लांट' स्थापित करने के संबंध में अभी हाल ही में हडको के मैटोरियल मैनेजर श्री सुरज जो वहा-दुर लखनऊ आये थे तथा इस संबंध में परिषद् एवं उत्तर प्रदेश सीमेंट कारपोरेशन के अधिकारियों से वार्ता की थी। उन्होंने सुझाव दिया है कि परिषद् द्वारा उत्तर प्रदेश सीमेंट कारपोरेशन के साथ मिलकर मिर्जापुर जिले में सीमेंटस प्लांट के समीप एक हाइड्रैटिड लाइम की फैक्ट्री स्थापित की जाय। इस प्रस्ताव पर अभी विचार किया जा रहा है।
- 5- स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया को 2 रेक्स लोहे के लेब की आपूर्ति का आदेश दिया गया था। भारत सरकार द्वारा हाल ही में लोहे की दरों में वृद्धि कर दिये जाने के फलस्वरूप 'सेल' ने अतिरिक्त मूल्य के भुगतान हेतु सहमति मांगी है। इस संबंध में विचार किया जा रहा है। प्राइवेट कमीशन एजेंट के माध्यम से मेन प्रोड्यूसर से सीधे लोहा प्राप्त करने के संबंध में शासन की अनुमति मांगी गई है।
- 6- लकड़ी की 'सेक्ण्डो सेरीज' तथा 'सीजनिंग-प्लान्ट' तथा प्राइवेट इन्टरप्रिजर को आदेश देने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।
- 7- 'विटमिन' की उपलब्धता के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राथमिकता प्राप्त करने के लिये सम्पर्क स्थापित किया गया एवं इसे प्राप्त किया जा रहा है। प्राथमिकता प्राप्त होने पर विटमिन शीघ्र प्राप्त होने की संभावना है।

*D. K. Singh*

### क्वालिटी कंट्रोल

मुख्यालय पर लेब स्थापित किये जा चुके हैं। अधिकारी योजनाओं में योजना थल पर भी इस तरह के छोटे लेब बनाये जा चुके हैं। इस का व्यापक प्रचार करवाया जाय तथा जनसाधारण को यह अवगत कराया जाय कि क्वालिटी कंट्रोल के लिये परिषद द्वारा क्या-क्या कदम उठाये जा चुके हैं।

परिषद ने निर्देश दिये कि सभी अधिकारियों को निदेश दिये जाय कि परिषद उत्कृष्ट Quality कार्य को उम्मीद करता है और किसी भी हालत में कार्य में अवरताओं को ग्रहण नहीं करेगी। परिषद ने चाहा कि प्रत्येक त्रैमास के अंत में रिपोर्ट प्रस्तुत हो कि गुण नियंत्रण कोष में इसे सुनिश्चित करने के लिये क्या-क्या किया है।

परिषद ने उपसमिति के निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया।

पुष्टि की गई

*Signature*

अध्यक्ष

18.8.81